



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 202-2021/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, DECEMBER 6, 2021 (AGRAHAYANA 15, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 6 दिसम्बर, 2021

संख्या 8/19/2021-4CII.— हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 149 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 87 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ) की अधिसूचना संख्या का०आ० 85/ह०अ० 16/1994/धा० 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं जो दिनांक प्रथम अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ) की अधिसूचना संख्या का०आ० 85/ह०अ० 16/1994/धा० 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में, पैरा 3 में, उप-पैरा (ix) के बाद, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(x) निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए निजी शैक्षणिक संस्थाओं हेतु सम्पत्ति कर पर शतप्रतिशत छूट स्वीकार्य होगी।”।

अरुण कुमार गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT****Notification**

The 6th December, 2021

No. 8/19/2021-4CH.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 87 read with Sub-section (1) of Section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (Act 16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O. 85/H.A. 16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013 with effect from 01.04.2021, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O. 85/H.A. 16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013, in para 3, after sub-para (ix), the following sub-para shall be inserted, namely:-

“(x) 100% rebate of property tax shall be admissible to Private Educational Institutions for the assessment year 2021-22.”.

ARUN KUMAR GUPTA,
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.